

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 30, शुक्रवार, शाके 1942-अगस्त 21, 2020 <i>Sravana 30, Friday, Saka 1942-August 21, 2020</i>	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत
करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 21, 2020

संख्या एफ. 13(20)विशा/विस/2020 :-राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन)
विधेयक, 2020 जैसा कि दिनांक 21 अगस्त, 2020 को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया
गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

2020 का विधेयक सं.20

राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम
बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय
संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 13 मई, 2020 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 168क का अंतःस्थापन.- राजस्थान माल और
सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) में विद्यमान धारा 168 के पश्चात् और विद्यमान
धारा 169 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"168क. विशेष परिस्थितियों में समय सीमा विस्तारित करने की सरकार की शक्ति.- (1) इस
अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उन
कार्रवाइयों के संबंध में, जिनको किसी अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण या जिनका अनुपालन नहीं किया जा
सकता, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट, या इसके अधीन विहित या अधिसूचित समय सीमा को विस्तारित कर
सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति में ऐसी अधिसूचना को किसी भी तारीख
से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की नहीं हो, भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने की शक्ति सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "अपरिहार्य घटना" से युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखे, अग्नि, चक्रवात, भूकंप या प्रकृति द्वारा या अन्यथा कारित किसी भी अन्य आपदा की दशा अभिप्रेत है, जिससे इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता है।"

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 3) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने के उद्देश्य से राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अधिनियमित किया गया था।

भारत सहित विश्व के कई देशों में कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए समय सीमा के विस्तार सहित कतिपय उपबंधों को शिथिल करने के उद्देश्य से राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में नयी धारा 168क अंतःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

चूंकि राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 13 मई, 2020 को राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 3) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 14 मई, 2020 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No.20 of 2020

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) BILL,
2020**

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 13th May, 2020.

2. Insertion of new section 168A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 168 and before the existing section 169 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the following new section shall be inserted, namely:-

"168A. Power of Government to extend time limit in special circumstances.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the time limit specified in, or prescribed or notified under this Act in respect of actions which can not be completed or complied with due to force majeure.

(2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the commencement of this Act.

Explanation.- For the purposes of this section, the expression "force majeure" means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act."

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 3 of 2020) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on *intra-State* supply of goods or services or both by the State Government.

In order to relax certain provisions including extension of time limit in view of the spread of pandemic COVID-19 across the many countries of the world including India, a new section 168A was proposed to be inserted in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 3 of 2020) on 13th May, 2020, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 14th May, 2020.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil kumar Mathur,
Secretary.

Government Central Press, Jaipur.